

रजिस्टर्ड नं ० एल०-३३/एस० एम०/ १३-१४/९५.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 15 नवम्बर, 1995/ 24 कातिक, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त (विनियम) विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, 19 सितम्बर, 1995

संख्या फिन-सी०-ए० (३)-४/९४.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 के साथ पठित धारा 98 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश पंचायत राज्य वित्त आयोग नियम, 1995 बनाते हैं जिनका सरकार की अधिसूचना संख्या ए० आई० एन०-सी०-ए० (३)-४/९४, तारीख 3-८-९४ द्वारा तारीख 2-९-९४ के राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में पूर्व प्रकाशन किया जा चुका है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम।—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायत राज्य वित्त आयोग नियम, 1995 है।

(२) गह ग्रन्थ प्रता होंगे।

२. परिभ्राष्टाएः—इन नियमों में, जब तक संस्कृत में वर्णाशास्त्राभिलापन न हो,

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अधिनियम है;

(ख) "वित्त आयोग" से पंचायतों के लिए अधिनियम की धारा ९४ के अर्द्धों गठित हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिष्ठित है;

(ग) "राज्यालय" से हिमाचल प्रदेश भरकार का राज्यालय अधिष्ठित है;

(घ) "मदस्थ" से वित्त आयोग वा मदस्थ अधिकार हैं और जिनके अन्तर्गत इयां अध्यक्ष भी हैं; और

(इ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अधिष्ठित है।

३. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति.—(१) हिमाचल प्रदेश सरकार, अधिनियम की धारा ९४ के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग के नाम से जालवा, राज्य वित्त आयोग को अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों को नियुक्ति करेगी,

(२) वित्त आयोग का मुख्यालय छिंगता में या ऐसे अन्य स्थान पर होता जैसा कि राज्य भरकार भूमि-भूमि पर अधिसूचित करे।

४. वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अहेनाह—वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी नियन्त्रित अहेनायें होगी :—

(क) पंचायतों से मन्त्रित आर्थिक और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव रखता हो।

या

(ख) नगरानिकाओं से मन्त्रित आर्थिक और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव रखता हो।

या

(ग) आर्थिक और प्रशासन मामलों का ज्ञान अनुभव रखता हो।

या

(घ) आर्थिक और प्रशासन मामलों का विशेष ज्ञान रखता हो।

५. वित्तीय या अन्य हित रखने वाले व्यक्तियों को वित्त आयोग के रूप में नियुक्त नहीं रिया जायगा,—(१) यस्कार, किसी ध्यक्ति को वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्त करन के लिए आना समाधान करनी कि ऐसा नियुक्त व्यक्ति, कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता है, जिसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष या मदस्थ के रूप में उनके अन्ते कुत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की अंगावता हो।

१०. विनीय आयोग के सचिव होने के लिए तिरंहार्थ, -कोई भी व्यक्ति, जिन आयोग के सचिव के रूप में नियमित लिये गए या होने वाले लिए तिरंवित होय, यदि वह :-

(क) विश्वा मित है,

(व) अनांत्रिक विनाशित है,

(ग) नीतिगत अधारों में प्रमुख विभिन्न आपगाथ में विद्वांसी उद्यगाता गया है।

(म) ऐसा विनीय या अन्य हित गवाना है जिसमें वित्त आयोग के उपरोक्त अपने कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की धर्मावशत हो।

७. मरम्पों की पदावधि—विन आगोंग ता प्रथमे मरम्प एक वर्षे के लिए पद धारण करेगा और पदावधि गायत्र मरकार द्वारा गायत्र-मरम्प पर गायत्रे में प्रकाशित अंदर्मूलना द्वारा प्राप्त वर्ग में इस के लिए वहाँ ता गकेगी परम्परा यह ही वर्षे ग अवधि हीगी ।

H. ऐसा की गर्ने और मनवयों के लेनन और भल्ने—(1) गत्ता विल आयोगके अध्यक्ष और मद्दय के तामां में नियमित गे पर्व उत्तर्वे जननवद करना होगा कि वह ऐसा किसीया या अन्य हित नहीं रखेगा किसे उपकी प्रयाणिति अथवा या मद्दय के स्था उपके अर्थों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की गंभीरता हो ।

(2) मरम्मां की मेवा को निवन्धन और यार्ने उनको प्राचारधि के द्वारा उनके अहित में परिवर्तित नहीं की जायेगी।

(3) ग्रन्थ वित्त आयोग का कोई कार्य या कार्यालयी केवल इस कारण में अविधिमान्य नहीं होती कि इसमें गदर्यों में से कोई रिकॉर्ड निबारात है या इसके गविधार में कोई लिपि है।

(4) राज निवृत्त आयोग के सदस्यों के बीच मनमेह होने की बांध में वृहमत को गय अधिभावी होनी और आयोग की गय और आवेदन वृहमत के चिनारों के ब्लू में अधिवक्ता किये जायेंगे।

(5) वित्तीय आयोग ने अदाख से वृक्षावधि योगी मणि के लिये 8,000 रुपए परि मास की दर से वेतन का संदर्भ किया जाएगा और निल आयोग के अन्य ग्रन्थांकी 4000 रुपए मध्येकन मानकर्य संबंध किया जाएगा।

परन्तु गवि विदा आगो का अद्यता आनी नियुक्ति के मात्रा भारत मरकार की या गंगा मरकार की या केवल गांगित प्रदेशों की मरकार में से किसी एवं जग के गम्भीर में (नियाकारा या भवित्वानि से नियन्ता) कोई वैधता प्राप्त नहीं है तो विल आगो में गंगा के लिये उपके बोतां में वे निम्ननियन्त्रित को पठा दिया जायेगा। अर्थात् :—

(क) उमा पीणन की रकम, और

(८) गर्व उसने ऐसी नियमित से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में भाने को देख प्रीति के पास भाग को बदले में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया है तो पैशन के उस भाग की रकम :

परन्तु यह और कि यदि सेवा निवृत्त श्रमित को विस्तृत प्रायोग के अवधि से अन्यथा सदस्य के रूप में नियमित किया जाता है तो वह पैशन और उस पर गणना-राशा पर अनुज्ञय भत्तों को पटा कर उसके द्वारा देवा के द्वौयान् प्राप्त अन्तिम वेतन प्राप्त करेगा ।

(९) वित्त आयोग का प्रध्यक्ष और प्रोफेशनल। प्रबंध सुलिङ्ग, नियुक्त राजार्थी आदास प्राप्त करने वाला उसके बदले में नियमित दरों पर भावार भर्ता प्राप्त करने का हकदार होगा :—

(१) अध्यक्ष	रु 2500/- प्रतिमाह
(२) कोई अन्य सदस्य	रु 500/- प्रतिमाह

(१०) इस नियम के उप-नियम (५) और (६) में किसी बात को होते हुये भी, प्रत्येक व्यक्ति जो अध्यक्ष से भिन्न सदस्य के रूप अपनी नियमित रोटरन्ट पूर्व राज्य सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी केन्द्र शासित प्रदेश के अधीन किसी पद पर हो, जब उन वह अधिकारियों की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या उक्त सरकार के अधीन उसकी राशि समाप्त नहीं हो जाती है, तब तब उसी दर और वेतनमान पर वेतन, भत्ते और वे ही अन्य सुविधाओं प्राप्त करता रहेगा । जिन्हें वह इन नियमित से पूर्व प्राप्त कर रहा था ।

(११) वित्त आयोग का अध्यक्ष अपने कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये गांधी और मंहगाई भत्ता उसी दर पर प्राप्त करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार के ग्रेड-I अधिकारी को अनुज्ञय है, और अध्यक्ष रोटरन्ट प्रत्येक सदस्य, अपने कर्तव्य पालन में की गई यात्रा गांधी मंहगाई भत्ते पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के निए उसी दर पर यात्रा और मंहगाई भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार ग्रेड-I अधिकारी को अनुज्ञय है ।

(१२) वित्त आयोग का प्रत्येक सदस्य उन्हीं चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा जो राज्य सरकार के ग्रेड-I अधिकारियों को अनुज्ञय है ।

(१३) अध्यक्ष का उप-नियम (५) के अधीन वेतन के अतिरिक्त भार सी रूपये प्रतिमाह की दर से सदस्य भत्ता संदर्भ में जाएगा ।

(१४) राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन मानदेय और अन्य संदेश भत्ते राज्य सरकार की समेकी नियम से संदर्भ में जाएंगे ।

१. वित्त आयोग को प्रक्रिया और शक्ति।—वित्त आयोग अपने कृतियों के प्रत्यालन को प्रक्रिया अवधारित करेगा और अधिनियम की धारा ९८ की उन्नारा (७) द्वारा उन प्रक्रियों पर प्रयोग करेगा ।

२. राज्य वित्त आयोग के कार्य दिवार प्रोटोकॉल।—राज्य वित्त आयोग के कार्य दिवार और कार्यालय समय वहीं होंगे जो सरकार के कार्यालयों के हैं/हों ।

३. राज्य वित्त आयोग की गोदान और गवर्नर।—राज्य वित्त आयोग की गोदान गोदान और संप्रतीक्षा गारे होगा जैसा राज्य सरकार विविध करे ।

12. राजत वित्त आयोग की बैठक।—राजत वित्त आयोग की बैठक जब भी अध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाएगी और वह कार्य की रूपान्व निपटान के हित में, अपनी अधिकारियों में, फिरी भी स्थान पर आपानों बैठकों का रखेगा।

13. राज्य वित्त आयोग के कर्मचारी।—राज्य सरकार, ऐसे कर्मचारियों की न्युक्ति करेगी जो आयोग को उसके दिन-प्रतिदिन वार्ष में गद्दयाल देने और ऐसे गृह्यता, जो उन अध्यक्ष द्वारा गोंपे जाए, वा अनुपालन करने के लिए आवश्यक हों। ऐसे कर्मचारियों का संदेश देना, राज्य सरकार की गमोकल निंदा में न चढ़ाया जाएगा।

14. पुनःनियुक्ति।—राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष और गद्दया, इन नियमों के नियम-7 में विविधिष्ट समय की समाप्ति पर पुनः नियुक्ति के लिए पाठ होंगे।

15. अध्यक्ष और गद्दस्यों का पद न हटाया जाना और ल्यापात्र।—(1) राज्य सरकार, अध्यक्ष या उनकी गद्दया को पद से हटा सकेगा, जो—

- (अ) न्यायनिर्णीत दीवालिया हो, या
- (ब) ऐसे अपराध से शोष लिया गया हो जो राज्य सरकार की राज में, नीतिक अप्रमाण से अन्तर्भूत हो, या
- (ग) अध्यक्ष के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये जारीरिका या पानीमा जा से अयोग्य हो, या
- (घ) ऐसा वित्तीय और अन्य हित अर्जित कर रखा हो, जिसमें उसके अध्यक्ष या गद्दस्य के गृह्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, या
- (ङ) अपने पद का इस प्रकार दृश्यप्रयोग किया हो जिसमें उसका पद पर वने रहना लोक हित में उन्नित न हो।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुये, अध्यक्ष या कोई गद्दस्य, उप-नियम के न्याय (घ) और (ङ) में विविधिष्ट आधारों पर पद से नहीं हटाया जाएगा जब तब राज्य सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया, जो वह विविधिष्ट करें, के अनुसार जांच नहीं कर जाती है और विधान वा कोई पदव्य उस प्राधारों पर दोपी नहीं पाया जाता है।

प्रादेश द्वारा,

कवर शमशेर शिह,  
वित्ताध्यक्ष एवं सचिव।

*[Authoritative English Text of the Notification No. Fin C (A) 191, dated 19-9-1995 as required under clause (3) or article 3(1)(c) of the Constitution of India]*

**FINANCE (REGULATION) DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

*Srinagar, the 19th September, 1995*

No. Fin C (A) 191. In exercise of the powers conferred by section 98, read with section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (1 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make after having been previously published in the Rajpatha Himachal Pradesh Extra Ordinary, dated 2nd September, 1994, the Government Notification No. Fin C (A) 191, dated 3-8-1994, the Himachal Pradesh State Finance Commission for Panchayats Rules, 1995, as under, namely:

**1. Short title.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Finance Commission for Panchayats Rules, 1995.

(2) These shall come into force at once.

**2. Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;

(b) "Finance Commission" means the Himachal Pradesh State Finance Commission for Panchayats constituted under section 98 of this Act;

(c) "Governor" means Governor of the State of Himachal Pradesh;

(d) "Member" means a member of the State Finance Commission and includes its Chairman; and

(e) "Government" means the Government of Himachal Pradesh.

**3. Appointment of Chairman and Members.**—(1) The Government of Himachal Pradesh shall appoint a Chairman and two other Members of the State Finance Commission to be called the Himachal Pradesh State Finance Commission for Panchayats under section 98 of the Act.

(2) The Finance Commission shall have its headquarters at Srinagar or at such other place as may be notified by the Government from time to time.

**4. Qualifications for appointment as Chairman and Members of the Finance Commission.**—The persons to be appointed as Chairman of the Finance Commission and as Members thereof shall—

(a) have special knowledge and experience in economic and financial matters relating to Panchayats; or

(b) have special knowledge and experience in economic and financial matters relating to Municipalities; or

(c) have wide experience in financial matters and in administration; or

(d) have special knowledge of economics.

**5. Persons having financial or other interests not to be appointed as Members of Finance Commission.** (1) Before appointing a person as a Chairman or Member of the Finance Commission, the Government shall satisfy itself that the persons so to be appointed has no financial or any other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Chairman or Member of the Finance Commission.

(2) After the appointment of Chairman and Members of the Finance Commission, the Government may also satisfy itself from time to time with respect to the Chairman and Members of the Finance Commission that they may have no financial or any other interest as is likely to affect prejudicially their functions as Chairman or Member of the Finance Commission and for that purpose the Government may require the Chairman and the Members to furnish it such information as it may consider necessary with a view to satisfy himself as to whether the Chairman or the Members have any such interests.

**6. Disqualification for being Members of the Finance Commission.** A person shall be disqualified for being appointed as, or for being a member of the Finance Commission,

- (a) If he is of unsound mind;
- (b) If he is an undischarged insolvent;
- (c) If he has been convicted of an offence involving moral turpitude; or
- (d) If he has such financial or any other interest as is likely to affect prejudicial his function as a Member of the Finance Commission.

**7. Term of office of Members.** Every Member of the Finance Commission shall hold office for one year and the term of office may be extended by a notification published in the Official Gazette at a time for six months, but not exceeding two years by the State Government.

**8. Conditions of Service and Salaries and Allowances of Members.** (1) Before appointment, the Chairman and Members of the State Finance Commission shall have to give an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such Chairman and Members, as the case, may be.

(2) The terms and conditions of service of the Members shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

(3) No Act or proceedings of the State Finance Commission shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy among its Members or any defect in the constitution thereof.

(4) In case of differences of opinion among the Members of the State Finance Commission the opinion of the majority shall prevail and the opinion or orders of the Commission shall be expressed in terms of the views of the majority.

(5) There shall be paid to the Chairman of the Finance Commission, in respect of the time spent on actual service, salary at the rate of Rs. 3000/- per month and other members of the Finance Commission a consolidated honorarium of Rs. 4000/- per month.

Provided that, if a Chairman of the Finance Commission at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State

or under the Government of Union Territory Administration, his salary in respect of service in the Finance Commission shall be reduced :

(a) by the amount of that pension ; and

(b) if he has, before such appointment, received in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service of the committed value thereto, by the amount of that portion of the pension :

Provided further that in case of retired person is appointed as member, other than the Chairman of the Finance Commission he shall draw the pay last draw by him minus pension plus allowances there on as admissible from time to time.

(6) The Chairman and every member of the Finance Commission shall be entitle to the use of rent free semi-furnished official residence or in lieu thereof house rent allowance at the following rates :—

(i) The Chairman .. Rs. 2,500 P.M.

(ii) Any other Members .. Rs. 500 P.M.

(7) Notwithstanding anything contain in sub-rule (5) and (6) of this rule, every person, who immediately before his appointment as Member, other than the Chairman, was holding any office under the Government of India or under the Government of any State or any Union Territory Administration shall be entitle to receive till he attains the age of superannuation or ceases to be in service under the said Government, the salary, allowances and other facilities at the same rates and scales at which he was drawing salary and allowances and availing the facilities, immediately before his appointment as such.

(8) The Chairman of the Finance Commission shall receive TA and DA to re-imburse him the expenses incurred by him on travelling on duty at the same rates as admissible to the highest Grade-I Officers of the State Government and every Members, other than the Chairman, shall receive TA and DA to re-imburse him the expenses incurred by him on travelling on duty at the same rates as admissible to the Grade-I Officers of the State Government.

(9) Every Members of the Finance Commission shall be entitle to the same medical facilities as are admissible to Grade-I Officers of the State Government.

(10) The Chairman in addition to his pay under sub-rule (5), shall also be paid sumptuary allowance at the rate of four hundred rupees per month.

(11) The expenses of the State Finance Commission on account of salaries honorarium and other allowances payable, in respect of the Consolidated Fund of the State Government.

**9. Procedure and Powers of Finance Commission.**—The Finance Commission shall determine its procedure in the performance of its functions and shall exercise the powers conferred upon it under sub-section 7 of section 98 of the Act.

**10. Working day and Office hours of the Finance Commission.**—The working days and office hours of the State Finance Commission shall be the same as that of the offices of the State Government.

**11. Seal and emblem of the State Finance Commission.**—The Official seal and emblem of the State Finance Commission shall be such as the State Government may specify.

**12. Sitting of the State Finance Commission.**—The Sitting of the State Finance Commission and when necessary, shall be convened by the Chairman and it may, in the interest of speedy disposal of the work, hold its sittings at any place within its jurisdiction.

**13. Staff of the State Finance Commission.**—The state Government shall appoint such staff as may be necessary to assist the State Finance Commission in its day-to-day work and to perform such functions as are assigned to it by the Chairman. The salary payable to such staff shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government.

**14. Re-appointment.**—The Chairman and the Members of the State Finance Commission shall be eligible for re-appointment on the expiry of the time specified in rule 7 of these rules.

**15. Removal of Chairman or Members from office and resignation.**—(1) The State Government may remove from office, the Chairman or any Member who:—

(a) has been adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as the Chairman or Member; or

(d) has acquired such financial or other interests as is likely to affect prejudicially his functions as the Chairman or a Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in the office prejudicial to the public interest.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Chairman or any Member shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d) and (e) of that sub-rule except on an enquiry held by the State Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf and find the Chairman or any Member guilty on such grounds.

By order,

Sd/-

*Financial Commissioner-cum-Secretary.*

---

निष्पत्रक, मुद्रा तथा लेखन सामग्री, हिंदूचत्र प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।